

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्गा/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 50]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 11 दिसम्बर 2020—अग्रहायण 20, शक 1942

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 3 जून 2020

क्रमांक ई-1-5/2020/एक/2.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री टामन सिंह सोनवानी भा.प्र.से. (सी.जी.-2004) द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु प्रस्तुत आवेदन दिनांक 30-05-2020 के प्रकाश में अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु-सह-सेवानिवृत्त प्रसुविधाएं) नियम, 1958 के नियम-16(2) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्धारित 90 दिवस की कालावधि में छूट प्रदान कर उन्हें अधिवार्षिकी आयु पूर्ण होने के पूर्व दिनांक 31-05-2020 (अपरान्ह) से सेवानिवृत्त करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कमलप्रीत सिंह, सचिव.

जल संसाधन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर 21 अक्टूबर 2020

क्रमांक 3483/7-ए/जसं./तशा/डी-4/औजप्र/01.—छत्तीसगढ़ सिंचाई अधिनियम-1931 (क्र.-3 सन् 1931) के अधीन विरचित नियमों के उपबंधों के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा-37 तथा 40 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए जल संसाधन विभाग की अधिसूचना क्रमांक-213/7-ए/जसं./तशा/डी-4/औजप्र/01, दिनांक 16-01-2020 को अधिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार एतद्वारा संपूर्ण राज्य में औद्योगिक प्रयोजन, ताप विद्युत तथा जल विद्युत परियोजनाओं के लिये निम्नलिखित जल-दर निर्धारित करती है :—

स.क्र.	उपयोग का प्रकार	विशेष विवरण	जल-दर	टीप
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	औद्योगिक प्रयोजन/ताप विद्युत प्रयोजन	अ शासकीय स्रोत :— 1 बांध/जलाशय/बैरॉज/एनीकट आदि से ... (i) शासकीय मद से निर्मित जल संग्रहण संरचना से... (ii) संस्थानों की अग्रिम जल-कर की राशि से निर्मित जल संग्रहण संरचना से... 2 नहर प्रणाली से..... ब नैसर्गिक स्रोत से :— (i) नदी/नाले आदि के बहाव से..... (ii) भू-जल से..... स स्वनिर्मित स्रोत से....	 रु. 10.50 प्रति घ.मी. रु. 10.50 प्रति घ.मी. रु. 12.25 प्रति घ.मी. रु. 5.00 प्रति घ.मी. रु. 10.00 प्रति घ.मी. रु. 3.50 प्रति घ.मी.	— — — — इस जल-दर पर प्राप्त जल-कर की शत प्रतिशत राशि, पृथक से निर्मित “भू-जल संरक्षण कोष” में जमा की जाए. इस कोष की राशि का उपयोग भू-जल संवर्धन (Recharging) आदि में किया जायेगा. —
2.	ऐसे उद्योग (जैसे-कोल्ड ड्रिक्स, मिनरल वॉटर, शराब आदि) जो जल का उपयोग कच्चे माल (Raw Material) के रूप में करते हैं...	अ शासकीय स्रोत :— 1 बांध/जलाशय/बैरॉज/एनीकट आदि से... (i) शासकीय मद से निर्मित जल संग्रहण संरचना से... (ii) संस्थानों की अग्रिम जल-कर की राशि से निर्मित जल संग्रहण संरचना से..... 2 नहर प्रणाली से..... ब नैसर्गिक स्रोत से :— (i) नदी/नाले आदि के बहाव से... (ii) भू-जल से..... स स्वनिर्मित स्रोत से....	 रु. 200.00 प्रति घ.मी. रु. 200.00 प्रति घ.मी. रु. 200.00 प्रति घ.मी. रु. 100.00 प्रति घ.मी. रु. 250.00 प्रति घ.मी. रु. 80.00 प्रति घ.मी.	इन जल-दरों पर प्राप्त जल-कर की शत प्रतिशत राशि, पृथक से निर्मित “भू-जल संरक्षण कोष” में जमा की जाए. इस कोष की राशि का उपयोग भू-जल संवर्धन (Recharging) आदि में किया जायेगा. —

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3.	जल विद्युत प्रयोजन (जल के उपयोग पश्चात् पुनः प्राप्ति) 25 मे.वा. से	अ शासकीय स्रोत :— 1 बांध/जलाशय/बैरॉज/एनीकट आदि से...	रु. 1.07 (एक रु. सात पैसे)/विद्युत इकाई उत्पादन एवं 200 (दो सौ) पैसे/100 वि.ई.उ. पर प्रति वर्ष एस्केलेशन चार्जेंस.	—
(क)	अधिक क्षमता की लघु जल विद्युत परि.	2 नहर प्रणाली से....	रु. 1.25 (एक रु. पच्चीस पैसे)/विद्युत इकाई उत्पादन एवं 250 (दो सौ पचास) पैसे/100 वि.ई.उ. उत्पादन पर प्रति वर्ष एस्केलेशन चार्जेंस	—
		ब नैसर्गिक/स्वनिर्मित स्रोत से....	रु. 0.35 (पैंतीस पैसे)/वि.ई.उ. पर.	—
(ख)	25 मे.वा. या उससे कम क्षमता की लघु जल विद्युत परियोजनायें	शासकीय/नैसर्गिक/स्वनिर्मित आदि विभिन्न स्रोत से....	रु. 0.06 (छः पैसे)	—

- उपरोक्तानुसार निर्धारित जल-दरें, इस अधिसूचना को जारी करने की तिथि (दिनांक 21-10-2020) से प्रभावशील रहेंगी.
- जल दरों का पुनर्निर्धारण समय-समय पर आवश्यकतानुसार किया जा सकेगा.
- औद्योगिक जल-दर निर्धारण संबंधी पूर्व की अधिसूचना, दिनांक 24-02-2016 की तालिका के स.क्र.-1 अ-1 (ii) “विशेष विवरण” अंतर्गत उल्लेखित “संस्थानों की अग्रिम जल-कर की राशि से निर्मित जल संग्रहण संरचना से....” की श्रेणी को विलोपित किया गया है. परंतु इस श्रेणी के अंतर्गत पूर्व से ही जिन संस्थानों को जल आबंटित है, या जो जल उपयोग कर रहे हैं हेतु, शासन की अधिसूचना दिनांक 24-02-2016 अनुसार इस श्रेणी हेतु निर्धारित जल-दर रु. 5.50/घ.मी. ही लागू रहेगी एवं इसका लाभ उन्हीं संस्थानों को प्राप्त होगा जिनके द्वारा, उनके हिस्से की निर्माण राशि एवं भू-अर्जन मुआवजा राशि का ब्याज सहित पूर्ण भुगतान कर दिया गया होगा. संबंधित संस्थान द्वारा विभाग में जमा अग्रिम जल-कर की राशि का, संस्थान द्वारा जल उपयोग प्रारंभ करने के पश्चात् नियमानुसार देय जल-कर की राशि में समायोजन किया जाएगा. तत्पश्चात् संबंधित प्रकरण में, इस अधिसूचना की तालिका के स.क्र.-1, कॉलम क्रमांक-3 के बिन्दु क्र.-1(i)-“शासकीय मद से निर्मित जल संग्रहण संरचना” अंतर्गत कॉलम क्रमांक-4 में प्रस्तावित जल-दर रु. 10.50 प्रति घन मीटर अथवा तत्समय में प्रचलित जलदर लागू होंगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वृन्दावन सेन, अवर सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बस्तर जगदलपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व विभाग

बस्तर, दिनांक 24 अक्टूबर 2020

क्रमांक क/भू-अर्जन/08/अ-82/2017-18.—भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापना में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (जिसे एतदपश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19(2) के तहत यह घोषित किया जाता है कि ग्राम कस्तूरी, प.ह.नं. 29, तहसील जगदलपुर, जिला-बस्तर की निजी भूमि के अर्जन से प्रभावित खातेदार/परिवार को निम्नानुसार पुनर्वास लाभ प्राप्त होगा.

क्रमांक (1)	खसरा नं. (2)	रकाब (हे.) (3)
01	विस्थापन की दशा में आवासन इकाईयों की व्यवस्था	लागू नहीं होता.
02.	भूमि के लिए भूमि	लागू नहीं होता.
03.	विकसित भूमि के लिए प्रस्थापना	लागू नहीं होता.
04.	वार्षिक या नियोजन का विकल्प	छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के निर्देश क्रमांक एफ-7-4/सात-1/2015/पार्ट, नया रायपुर दिनांक 29-08-2016 में निहित निर्देश/प्रावधान अनुसार भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की अनुसूची दो की कण्डिका 04 का लाभ पात्र प्रभावित खातेदार/परिवार को प्राप्त होगा.
05.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन-निर्वाह अनुदान.	लागू नहीं होता.
06.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	लागू नहीं होता.
07.	पशु बाड़ा/छोटी दुकान खर्च	लागू नहीं होता.
08.	कारीगरों छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एक बारगी अनुदान.	लागू नहीं होता.
09.	मछली पकड़ने का अधिकार	लागू नहीं होता.
10.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	लागू नहीं होता.
11.	स्टाम्प शुल्क और रजिस्ट्रीकरण फीस	लागू नहीं होता.

1- तदनुसार आज दिनांक 24/10/2020 को यह घोषणा पत्र जारी किया जाता है.

बस्तर, दिनांक 24 अक्टूबर 2020

क्रमांक क/भू-अर्जन/09/अ-82/2017-18.—भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापना में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (जिसे एतदपश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19(2) के तहत यह घोषित किया जाता है कि ग्राम-

मंगनपुर, प.ह.नं. 26, तहसील जगदलपुर, जिला-बस्तर की निजी भूमि के अर्जन से प्रभावित खातेदार/परिवार को निम्नानुसार पुनर्वास लाभ प्राप्त होगा.

क्रमांक (1)	खसरा नं. (2)	रकाब (हे.) (3)
01	विस्थापन की दशा में आवासन इकाईयों की व्यवस्था	छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के निर्देश क्रमांक एफ 7-4/सात-1/2015/पार्ट, नया रायपुर दिनांक 29-08-2016 में निहित निर्देश/प्रावधान अनुसार भू-अर्जन अधिनियम 2013 की अनुसूची दो की कण्डिका 01(1) का लाभ पात्र प्रभावित खातेदार/परिवार को प्राप्त होगा.
02.	भूमि के लिए भूमि	लागू नहीं होता.
03.	विकसित भूमि के लिए प्रस्थापना	लागू नहीं होता.
04.	वार्षिक या नियोजन का विकल्प	छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के निर्देश क्रमांक एफ-7-4/सात-1/2015/पार्ट, नया रायपुर दिनांक 29-08-2016 में निहित निर्देश/प्रावधान अनुसार भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की अनुसूची दो की कण्डिका 04 का लाभ पात्र प्रभावित खातेदार/परिवार को प्राप्त होगा.
05.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन-निर्वाह अनुदान.	छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के निर्देश क्रमांक एफ-7-4/सात-1/2015/पार्ट, नया रायपुर दिनांक 29-08-2016 में निहित निर्देश/प्रावधान अनुसार भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की अनुसूची दो की कण्डिका 05 का लाभ पात्र प्रभावित खातेदार/परिवार को प्राप्त होगा.
06.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के निर्देश क्रमांक एफ-7-4/सात-1/2015/पार्ट, नया रायपुर दिनांक 29-08-2016 में निहित निर्देश/प्रावधान अनुसार भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की अनुसूची दो की कण्डिका 06 का लाभ पात्र प्रभावित खातेदार/परिवार को प्राप्त होगा.
07.	पशु बाड़ा/छोटी दुकान खर्च	लागू नहीं होता.
08.	कारीगरों, छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एक बारगी अनुदान.	लागू नहीं होता.
09.	मछली पकड़ने का अधिकार	लागू नहीं होता.
10.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के निर्देश क्रमांक एफ-7-4/सात-1/2015/पार्ट, नया रायपुर दिनांक 29-08-2016 में निहित निर्देश/प्रावधान अनुसार भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की अनुसूची दो की कण्डिका 10 का लाभ पात्र प्रभावित खातेदार/परिवार को प्राप्त होगा.
11.	स्टाम्प शुल्क और रजिस्ट्रीकरण फीस	लागू नहीं होता.

1- तदनुसार आज दिनांक 24/10/2020 को यह घोषणा पत्र जारी किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रजत बंसल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला-रायगढ़ (छत्तीसगढ़), एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग**

रायगढ़, दिनांक 29 अक्टूबर 2020

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 32/अ-82/2018-19.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जावेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	बंगुरसिया प.ह.नं. 21	0.659	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, रायगढ़ संभाग जिला-रायगढ़ (छ.ग.).	रायगढ़-हमीरपुर मार्ग निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भीम सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला जशपुर, छत्तीसगढ़ एवं
पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग**

जशपुर, दिनांक 1 अक्टूबर 2020

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 13/अ-82/2018-19.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—	
(क) जिला-जशपुर	
(ख) तहसील-पत्थलगांव	
(ग) नगर/ग्राम-चौराआमा	
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.364 हेक्टेयर	
खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
198/2	0.101
197/1/क	0.182

(1)	(2)	(1)	(2)
198/1	0.081	677	0.121
योग	03	योग	13
	0.364		1.245
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-घरजियांबंधान जलाशय के डूबान का पूरक भू-अर्जन प्रकरण.		(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-लोकेर जलाशय योजना के दांयी तट शाखा नहर का भू-अर्जन प्रकरण.	
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पत्थलगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.		(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पत्थलगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.	

जशपुर, दिनांक 1 अक्टूबर 2020

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 28/अ-82/2018-19.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

- (क) जिला-जशपुर
- (ख) तहसील-पत्थलगांव
- (ग) नगर/ग्राम-रेडे
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.245 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
696	0.093
697	0.012
698	0.061
717	0.045
718	0.081
719	0.121
720	0.210
736	0.129
737	0.121
743/1	0.126
743/2	0.060
676	0.065

जशपुर, दिनांक 1 अक्टूबर 2020

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 33/अ-82/2018-19.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

- (क) जिला-जशपुर
- (ख) तहसील-पत्थलगांव
- (ग) नगर/ग्राम-खरकट्टा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.150 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
644/1	0.095
645/1	0.310
647/1	0.008
647/2	0.110
663	0.040
668/2	0.050
682/1	0.192
681	0.004
16/15	0.222
67	0.012
737	0.150
679/2	0.024

(1)	(2)	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-खरकट्टा जलाशय योजना के डूबान एवं दांयी बांयी मुख्य नहर पूरक का अनिवार्य भू-अर्जन प्रकरण.
61/2	0.024	
684/1	0.060	
743/1ख	0.045	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पत्थलगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.
742	0.170	
68/3घ	0.020	
76/1	0.008	छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
55/3	0.063	महादेव कावरे, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.
679/1	0.008	
683	0.143	कार्यालय, कलेक्टर, जिला बस्तर, जगदलपुर,
680	0.014	छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,
16/19ख/4	0.120	राजस्व विभाग
16/5	0.238	
77	0.016	
56/1	0.012	बस्तर, दिनांक 24 अक्टूबर 2020
55/7	0.076	
55/6	0.034	क्रमांक/क/भू-अर्जन/08/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—
657/2	0.024	
36/1ख	0.004	
394	0.080	
641/5	0.080	
648/2	0.080	
648/1	0.008	
650	0.054	अनुसूची
688	0.050	
743/1घ	0.264	(1) भूमि का वर्णन—
738	0.101	(क) जिला-बस्तर
744	0.120	(ख) तहसील-जगदलपुर
73	0.008	(ग) नगर/ग्राम-कस्तूरी
74/1	0.032	(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.44 हेक्टेयर
655	0.004	
56/2	0.180	खसरा नम्बर
656	0.080	रकबा
652	0.079	(हेक्टेयर में)
36/1ग	0.012	(1) (2)
16/1क/2	0.066	88/1 0.120
16/18	0.104	88/2 0.400
16/17ख/2	0.060	88/3 0.410
664	0.004	88/4 0.120
68/3ख	0.110	88/5 0.160
68/3छ	0.040	89/1 0.050
55/2ज	0.040	89/2 0.050
55/2झ	0.064	89/3 0.040
		89/4 0.040
		89/5 0.040
		96/1 0.610
योग	55 4.150	

(1)	(2)	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
96/2	0.200	(1)	(2)
96/3	0.200		
योग	13	47	0.160
		51	0.440
		52	0.120
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-एनएमडीसी 3.00 एमटीपीए इन्टीग्रेटेड स्टील प्लांट के निर्माण हेतु.		57/1	0.060
		57/2	0.060
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जगदलपुर जिला-बस्तर के कार्यालय में किया जा सकता है.		57/3	0.060
		58/1	0.110
		58/2	0.100
		58/3	0.100
बस्तर, दिनांक 24 अक्टूबर 2020		58/4	0.100
		58/5	0.100
क्रमांक/क/भू-अर्जन/09/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—		59	0.450
		68	0.400
		83	0.080
		योग	14
			2.340
		(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-एनएमडीसी 3.00 एमटीपीए इन्टीग्रेटेड स्टील प्लांट के इन प्लांट रेल्वे लाईन निर्माण हेतु.	
		(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जगदलपुर जिला-बस्तर के कार्यालय में किया जा सकता है.	
		छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रजत बंसल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.	

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—
- (क) जिला-बस्तर
 - (ख) तहसील-जगदलपुर
 - (ग) नगर/ग्राम-मंगनपुर
 - (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.34 हेक्टेयर

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमा, रायपुर (छ.ग.)

रायपुर, दिनांक 10 नवम्बर 2020

क्रमांक/1178/रीडर/अ.भू.अ./2020.—सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग रायपुर के पत्र क्रमांक एफ-6-62/2008/सात-3/रायपुर दिनांक 03-09-2009 में दिए गए निर्देशानुसार नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियमन) निरसन अधिनियम 1999 की धारा 3 एवं 4 के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कर्तव्यों के निर्वहन के लिए श्री एन. आर. साहू (रा.प्र.से.) अपर कलेक्टर रायपुर को अधिकृत किया जाता है.

डॉ. एस. भारतीदासन,
कलेक्टर.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

No. 6102/Rules/2020

Bilaspur, the 10th July 2020

RULES FOR ON-LINE ELECTRONIC FILING (E-FILING) FRAMED UNDER ARTICLE 225 AND 227 OF THE CONSTITUTION OF INDIA

Short Title, Applicability and Commencement :

These Rules will be called “e-filing Rules, 2020”. They will be applicable to the High Court of Chhattisgarh and to the District Courts and Tribunals over which it has supervisory jurisdiction. These Rules will come into force from the date notified by the High Court.

1. Preface :

These Rules will apply to on-line e-filing and e-filing through Designated Counters and facilities provided for e-filing, including e-Service Centres. The rules will apply to such categories of cases as would be notified by the High Court. These Rules amend and consolidate the existing Rules and Practice Directions.

2. Definitions :

- 2.1 **Action** : includes all proceedings instituted in the Court such as suits, criminal complaints, appeals, civil or criminal writ petitions, revision petitions, contempt petitions, execution petitions, arbitration petitions, probate cases and interlocutory applications.
- 2.2 **Administrator** : means the Registrar (IT)/(Computerization) or an officer appointed by the Chief Justice for administering and dealing with matters connected with or relating to e-filing.
- 2.3 **Bench** : means and includes one or more judges assigned to adjudicate upon Actions or the presiding officer of the Court or Tribunal as the case may be.
- 2.4 **Physical Filing** : means Actions and pleadings filed as hard copies.
- 2.5 **Designated Counters** : means and includes those counters which find mention in Appendix-I and those that may be included or excluded from Appendix-I from time to time.
- 2.6 **District Courts** : means and includes the courts established and functioning under the control and supervision of the High Court.
- 2.7 **Electronic Filing (e-filing)** : means e-filing as prescribed through the Internet (at the web portal of the Court) and through the internet/intranet at Designated Counters, unless the context requires otherwise.
- 2.8 **Evidence** : means and includes evidence as defined under the Indian Evidence Act, 1872.
- 2.9 **High Court** : High Court means the High Court of Chhattisgarh.
- 2.10 **Objections** : means and includes deficiencies and errors pointed out by the Registry or Court/Competent Authority in relation to the Actions instituted in the Court.
- 2.11 **Opposite Party** : means defendant(s), respondents, judgment debtor(s) and non-applicant(s).
- 2.12 **Party** : means appellant(s), plaintiff(s), petitioner(s), complainant(s) and applicant(s).
- 2.13 **Pleadings** : means pleadings filed in support or defence of an Action including affidavits, additional affidavits and supplementary affidavits.

- 2.14 **PDF** : means an electronic document filed in a portable document format.
- 2.15 **PDF/A** : means an ISO-standardized version of the Portable Document Format (PDF) specialized for the digital presevation of electronic documents.
- 2.16 **Registry**: means the Registry of the Court.
- 2.17 **Statement of Defence** : means and includes written statements, replies, counter-affidavits and additional or supplementary affidavits.
- 2.18 **Technical failure** : means a failure of the court's hardware, software, and/or telecommunications facility which results in the impossibility of submitting a file electronically. Technical failure does not include malfunctioning of the equipment of the person submitting an e-file.
- 2.19 **Third Party** : means and includes any person or entity seeking to become a party or to intervene in an Action.
- 2.20 **Working Day** : means and includes a day when the Registry of the Court is working under the Calendar published or as directed by the Court.
3. **General Instructions :**
- 3.1 On-line e-filing shall be made by visiting the web portal of the Court, namely :
<https://www.efiling.ecourts.gov.in/cg>
- 3.2 Except as provided in these Rules, Actions, whether in fresh, pending or disposed of cases, will be filed electronically by an advocate or litigant in person from their home, office or other remote location in the manner provided in these Rules.
- 3.3 Any person who is unable to access the e-filing portal would be entitled to make use of the facilities provided at the Designated Conuters for that purpose upon payment of charges if stipulated.
- 3.4 The size of the e-file should not exceed 20MB. In case the file size exceeds 2 MB. the Advocate or litigant should visit any one of the Designated Centres for enabling e-filing through the intranet, or it can be split and uploaded separately.
4. **Steps for Registration :**
- 4.1 Persons other than Advocates and litigants in person who are already registered on the Court web portal will take the following steps to register themselves.
- i) **Advocates**
- a) Should visit the web portal (**<https://www.efiling.ecourts.gov.in/cg>**) to view the form.
- b) Click the registration link.
- c) Fill the form with requisite details.
- d) Submit the filled-up form along with a self-attested copy of the Bar Council Registration Certificate or Bar Council I-card (in PDF format only).
- ii) **Litigants in person**
- a) Should visit the web portal (**<https://www.efiling.ecourts.gov.in/cg>**) to view the form.
- b) Click the registration link.
- c) Fill the form with requisite details.
- d) Submit the filled-up form along with the self-attested copy of any identity document issued by the Government (in PDF format only).
- 4.2 Litigants in person shall submit an affidavit/undertaking that they have not engaged an Advocate in the Action. A litigant in person who subsequently engages an Advocate, shall make an application before the Administrator for transferring the data in respect of the Action to the Advocate's account

in. Once the Administrator allows the application, the data in the Action shall be transferred in the user account of the Advocate. The litigant in person will not be in a position to modify the data of the subject Action, without the permission of the Administrator.

- 4.3 A login ID will be allotted on the next working day if the application is found complete in all respects. The procedure for registration is set out in Appendix-II.

5. **Frame of Pleadings :**

The pleadings should be clear and concise. parties and third parties should set forth their claims/averments in separate paragraphs. The statement of truth/affidavit of the concerned person must bear their signature. Opposite parties should also file their replies under sequentially numbered paragraphs and headings (such as Preliminary objections and Objections on Merits).

6. **Formatting :**

- 6.1 All the original typed text material including notice of motion, memorandum of parties, main petition or appeal, interlocutory application(s), reply, status report, affidavit, documents, will be prepared electronically using the following formatting style:

- Paper size : **Thick Green Paper of Foolscap Size**
- Top Margin : 1.5"
- Bottom Margin : 1.5"
- Left Margin : 1.75"
- Right Margin : 1.0"
- Alignment : Justified
- Font : Times New Roman, Arial, Baskerville, Book Antigua, Bookman, Bookman Old Style, Century, Century Schoolbook, Courier, Courier New, CGTimes, Garamond, Georgia, New Baskerville, New Century Schoolbook, Palatino and the typeface shall be 14-point or larger in both body text and footnotes.
- Font size : 14
- Line spacing : 2.0
- If any document is typed in a local language in Trial Courts, it must be in prepared using Unicode Font 14 as prescribed time to time.

- 6.2 The document should be converted into Optical Character Recognition (OCR) searchable Portable Document Format (PDF) or PDF/A using any PDF converter or in-built PDF conversion plug-in provided in the software, PDF/A is the preferred format in A4 size.

- 6.3 A document which is not a text document and has to be enclosed with the Action, should be scanned using an image resolution of 300 DPI (Dots per inch) in OCR searchable mode and saved as a PDF document in A4 size. The procedure for converting a document into an OCR searchable PDF as mentioned above and as required in clause 8.1 is set out in Appendix-III.

7. **Digital Signatures :**

- 7.1 The PDF document shall be digitally signed either by the parties and/or by their Advocate. The digital signatures shall be appended on such places on the PDF document as prescribed under the extant rules. If neither the party nor the Advocate who has been engaged possess a digital signature, a print out of the Action shall be physically signed by the party concerned and/or their Advocate in accordance with rules and it shall thereafter be scanned and uploaded.

- 7.2 A List of recognized Digital Signature Providers and the procedure involved in appending single or multiple signatures is set out in Appendix-IV.
- 7.3 A litigant in person or advocate who does not possess a digital signature issued by the competent authority can authenticate e-filed documents by e-Sign based on Aadhaar authentication.

8. **Dos and Don't's**

- 8.1 The text documents and scanned documents set out in clauses 6.3 and 7.1 should be merged as a single OCR searchable PDF file and should be book-marked as per the Master Index, duly approved by the Registry. The procedure in this behalf is set out in Appendix-V.
- 8.2 The merged documents should be uploaded at the time of on-line e-filing. Screenshots of the manner of accessing the on-line e-filing portal and for the filing of the main case and documents including written statements, replies, replications, rejoinders, affidavits and evidence in a pending case are set out in Appendix-I.
- 8.3 Once e-filing is accepted, the filing or registration number shall be notified to the Advocate or litigant in person.
- 8.4 In case on-line e-filing includes audio and/or video files, the Administrator shall generate a hash value.
- 8.5 Special characters are not allowed while e-filing Memo of Parties and Advocate remarks.
- 8.6 Document Binary File Name Standards.

The following special characters are not allowed in a file name :

- A quotation mark (“ ”)
- A number sign/Pound (#)
- Per cent (%)
- Ampersand (&)
- Asterisk (*)
- Colon (:)
- Angle brackets (less than, greater than) (< >)
- A question mark (?)
- Backslash (\)
- Forward slash (/)
- Braces (left and right) ({ })
- Pipe (|)
- A tilde (~)
- The period (.) character used consecutively in the middle of the file name or at the beginning or end of the file name.

File names should not exceed 45 characters in length, including spaces. Single space must be counted as one character each.

- 8.7 On-line e-filing shall not be watermarked or encrypted. The e-filed documents shall not contain any virus, malware, spam-ware, trojan horse or the like. All the e-filed documents shall be legible and free of markings, track changes or annotations.

9. **Payment of Court Fees/Other Charges:**

Court fee and other charges can be paid either electronically by purchase on the on-line facility provided by the authorised agency or from the Designated Counters provided for the purpose in the High Court and District Courts or from any authorized court fee vendor. The Transaction ID provided upon payment of court fee and other charges is required to be entered in the appropriate field at the time of on-line e-filing.

10. **Retention of Originals:**

- 10.1 Originals of the documents that are scanned and digitally signed by the Advocate or the litigant in person at the time of e-filing should be preserved, for production or inspection, as may be directed by the Bench.

- 10.2 The signed vakalatnama, signed and notarized/attested affidavit and any other document whose authenticity is likely to be questioned should be preserved, at least, for two years till after the final disposal of the Action. Final disposal shall include disposal of the Action by the superior appellate court.

- 10.3 Notwithstanding anything above, the following documents will have to be preserved permanently :—

- a) A Negotiable Instrument (other than a cheque) as defined in Section 13 of the Negotiable Instruments Act, 1881 (26 of 1881).
- b) A Power-of-Attorney as defined in section 1A of the Powers-of-Attorney Act, 1882 (7 of 1882).
- c) A Trust as defined in Section 3 of the Indian Trusts Act, 1882 (2 of 1882).
- d) A Will as defined in Clause(h) of Section 2 of the Indian Succession Act, 1925 (39 of 1925) including any other testamentary disposition by whatever name called.
- e) Any contract for the sale or conveyance of immovable property or any interest in such property.
- f) Any other document as may be directed by the Bench.

- 10.4 The responsibility of producing the originals and proving their genuineness shall be of the party that has electronically filed scanned copies of the document.

11. **Access to the Electronic Data of the Action:**

Access free of cost access will be available to authorized person(s) to data e-filed by any of the parties to the specific Action, as is presently being provided in pending Actions. This facility shall be in addition to the procedure of obtaining certified copies.

12. **Exemption from e-filing:**

Exemption from on-line e-filing of the entire pleading or a part of the pleadings and/or documents may be permitted by the Bench upon an application being made for that purpose in the following circumstances:

- i) where on-line e-filing is for reasons set out in the application not feasible;or
- ii) where there are concerns about confidentiality and protection of privacy;or
- iii) where the document cannot be scanned or filed electronically because of its size, shape or condition; or
- iv) where the on-line e-filing portal is either inaccessible or not available for some reason;and/or
- v) for a just and sufficient cause.

13. Service of Electronic Documents:

In addition to the prescribed mode of service, notices, documents, pleadings that are filed electronically may also be served through the designated e-mail IDs of Registry officials to the e-mail address of the advocates or parties, if available. E-mail IDs of Registry officials will be published on the Court website to enable the recipients to verify the source of the e-mail.

14. Computation of Time:

14.1 Wherever limitation/time limits apply, it will be the responsibility of the party concerned to ensure that the filing is carried out well before the cut-off date and time. The date of e-filing will be taken as that date when the Action is electronically received in the Registry within the prescribed time on any working day. For computing the time at which e-filing is made, Indian Standard Time (IST) will apply.

14.2 E-filing through Designated Counters will be permissible up to 1600 hours on any court working day. On-line e-filing carried out after 1600 hours on any day, will be treated as the date which follows the actual filing date provided it is a court working day. Actions filed on a day declared as gazetted holiday or on a day when the court is closed, will be regarded as having been filed on the next working day. For the computation of limitation, on-line e-filing shall be subject to the same legal regime as applicable to physical filing, save and except as provided herein above.

14.3 The facility for on-line e-filing through the web portal shall be available during all twenty four hours of each day, subject to breakdown, server downtime, system maintenance or such other exigencies. Where on-line e-filing is not possible for any of the reasons set out above, parties can either approach the Designated Counters for e-filing between 10.00A.M. to 05.00 P.M. on court working days or take recourse to physical filing. No. exemption from limitation shall be permitted on the ground of a failure of the web based on-line e-filing facility.

14.4 Provisions for limitation governing on-line e-filing will be the same as those applicable to physical filing. The period of limitation for such actions will commence from the date when e-filing is made as per the procedure prescribed in these Rules.

15. Procedure for filing Caveat:

All caveats can be filed on-line. The procedure for this purpose is set out in Appendix-VI.

16. Hard Copies of Pleadings and Documents filed Electronically:

Advocates, as well as parties, may print hard copies of all pleadings and documents filed electronically for their use in the court or elsewhere. The Registry will wherever required prepare hard copies for official use.

17. Storage and Retrieval of e-Filed Documents and Pleadings:

E-filings will be stored on an exclusive server maintained under the control and directions of the Court. Each such filing will be separately labelled and encrypted for facilitate easy identification and retrieval. The security of such filings will be ensured. Access to e-filing would be restricted in the manner provided herein above and as may be notified from time to time. For continuity of operations in case of disaster, natural calamity or breakdown, a mirror image of e-filings available on the servers located in the Court may be maintained at different geographical locations, as decided from time to time by the Court.

18. Residuary provisions:

18.1 The e-filing made by an Advocate/litigant in person will be rejected if they do not follow the protocol mandated by these Rules or practice directions.

18.2 Subject to such further directions as may be issued, it would not be obligatory on the part of the opposite party to accept pleadings and documents by email. In such an eventuality, hard copies of pleadings and documents will have to be provided to the opposite party. In such circumstances, the plaintiff/petitioner can be called upon to deposit the charges calculated on the basis of the number of pages per defendant/respondent which are required to be photocopied. This facility will be provided by the Registry on a written request being made by the defendant(s)/respondent(s).

18.3. The Registry will communicate the objections, if any, regarding the cases filed by email/SMS/web hosting to the concerned Advocate/litigant in person. After the objections are cleared the case will be processed for listing and the Advocate/litigant in person will be informed including by e-mail/SMS.

19. **General Caution:**

Email is not a secure medium of communication. Any communication transmitted by e-mail can be intercepted or read by a third party. An Advocate or litigant in person seeking to transmit confidential or sensitive document/material, shall approach the Registry for requisite assistance/advice.

Appendices

APPENDIX — I

Screenshots showing the procedure for accessing the on-line portal, electronic filing of documents and list of Designated Counters.

APPENDIX — II

Screenshots showing the procedure for registration.

APPENDIX — III

Screenshots showing the procedure for converting a document into an OCR searchable PDF.

APPENDIX — IV

Screenshots showing the procedure for appending single or multiple digital signatures.

APPENDIX — V

Screenshots showing the procedure for book-marking.

APPENDIX — VI

Screenshots showing the procedure for filing Caveat.

By order of Hon'ble the High Court,
NEELAM CHAND SANKHLA, Registrar General.

A STEP BY STEP GUIDE FOR EFILING

(efiling for High courts & District Courts of India)



**Circulated by
e committee
Supreme Court of India**

Table of Contents

1.1.Introduction.....	1
1.2.Getting Started.....	1
1.3. E.Filing portal www.efiling.ecourts.gov.in.....	1
1.4. Select your< state>.....	2
1.5.Login.....	2
1.5.1. Forgot password :.....	2
1.6. Dashboard :.....	2
1.6.1. My e filing status:.....	3
1.6.2 My e filed cases:.....	3
1.7.New case option:.....	3
1.8. Where to file High court /Lower court:.....	4
1.9.Filling up of forms:.....	4
1.9.1.Colour coding:.....	4
1.9.2. Complainant/Petitioner form:.....	5
1.9.3.E-filing number:.....	5
1.9.4. Respondent form:.....	6
1.9.5. Extra information Form (optional):.....	6
1.9.6. Extra Party Details :.....	7
1.9.7 Case Details:.....	7
1.9.7.1. Hide Party:.....	8
1.9.8. Act-Section:.....	8
1.9.9.Signing Method:.....	8
1.9.10. Upload Document:.....	9
1.9.11.Pay court fees:.....	10
1.9.12 Affirmation and Verification of Applicant.....	10
1.9.13. Advocate Identification and Verification:.....	11
1.9.14 . View:.....	11
1.10. Final submit:.....	11
1.11. Submitted for approval of e filing admin :.....	12
1.12.Generate acknowledgment:.....	12
1.13. Generate Case party details:.....	13
1.14. Logout:.....	14
1.15.Conclusion:.....	14

A Step by Step Guide for E-filing

(For High courts & District Courts of India)

1.1.Introduction

Welcome to the digital world of E-filing of High courts /District courts of India and this user guide will help you with step by step how to efile your case in the online efilng portal. Follow this step by step guide and Start E-filing your cases from the comfort of your Office and And join the new band of **DIGITAL ERA ADVOCATE** .

1.2.Getting Started

- Before starting efilng confirm and ensure the following details:
- You must be a registered Advocate in www.efiling.ecourts.gov.in
- If you are not a registered Advocate, immediately register today in the efilng portal by watching our helpline tutorial/manual.
- To Watch the Help video / manual click on this hyperlink <https://efiling.ecourts.gov.in/help>.
- Unless you are a registered user you cannot efile a new case
- Keep you registered user name and Password ready. Lets start efilng a new case
- Lets start e filing a new case .

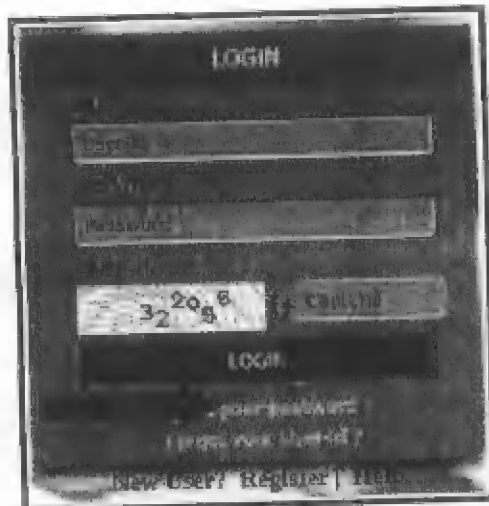
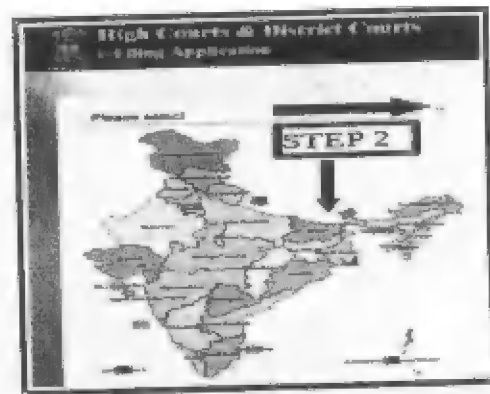
1.3. E.Filing portal www.efiling.ecourts.gov.in

Type (www.efiling.ecourts.gov.in) in your browser you will reach the filing online portal.



1.4. Select your< state>

- (i) by clicking on the drop list (or)
- (ii) by clicking the state directly from the India map

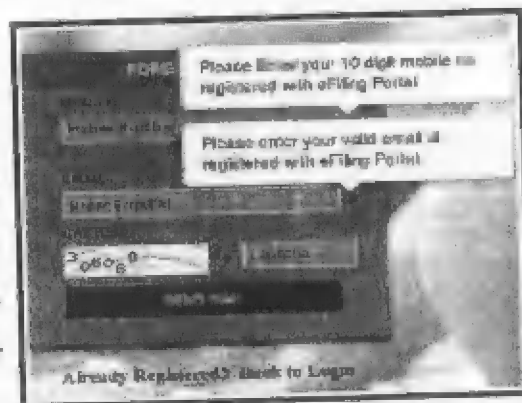


1.5.Login

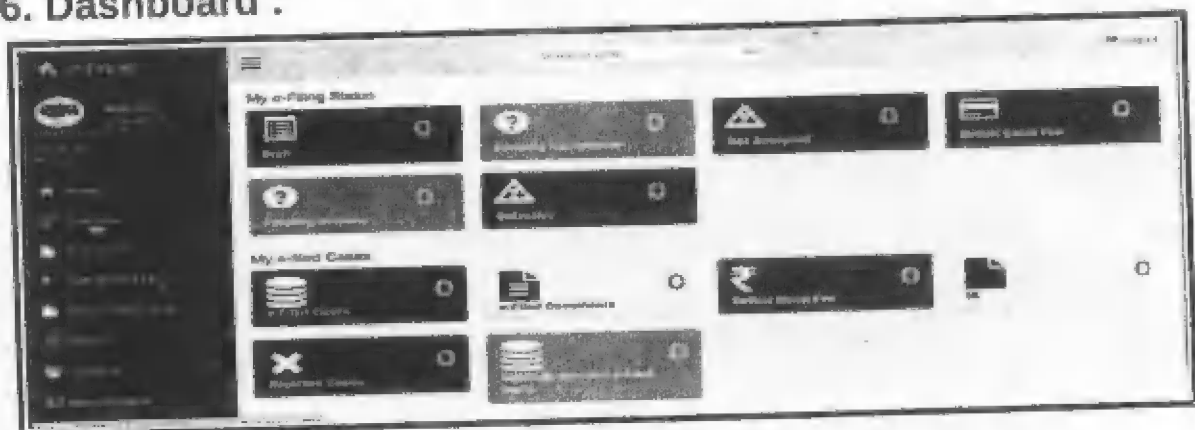
- Type the login id and password
- Enter the captcha
- Click on **LOGIN** button.

1.5.1 Forgot password :

If you forget your password or User-Id, you can click on the same and can enter your 10 digit mobile number or valid email id which you had registered with e Filing Portal at the time of Registration and then reset your password..

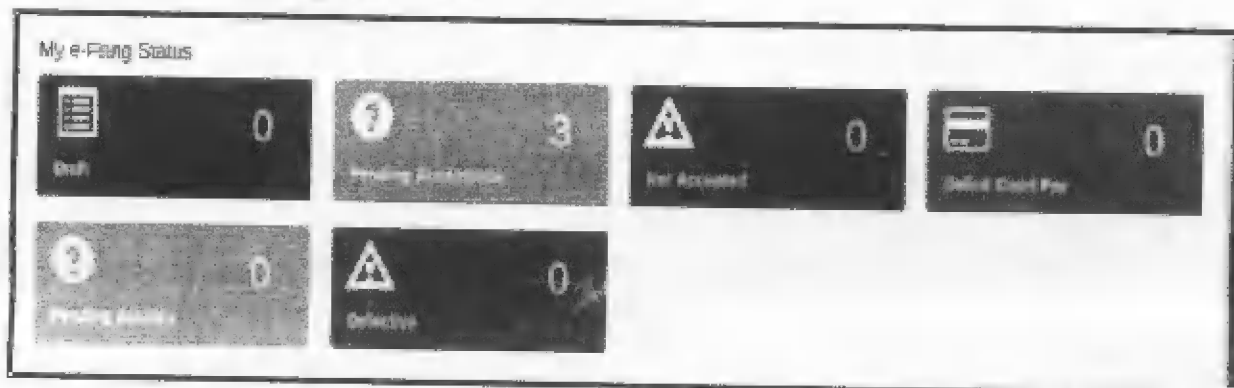


1.6. Dashboard :



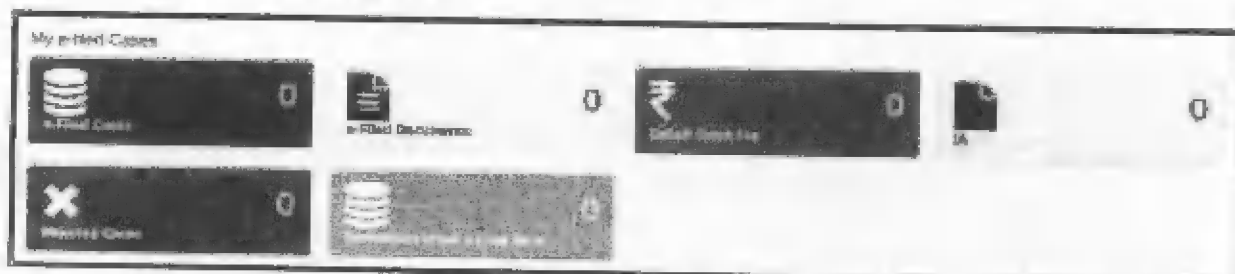
Dash board is the most important page from where you can keep track of the e filed cases digitally under two head (a) My e filing status and (b) My e filed cases. Let us see one by one.

1.6.1. My e filing status:



The e filing status shows the cases pending for acceptance , the cases not accepted, cases which have deficit court fees the cases pending for scrutiny and which are defective. There is another wonderful option under Draft where you can store all your drafts which are ready for e filing .

1.6.2 My e filed cases:



Under e filed cases you can see your list of e filed cases, e filed documents, deficit court fee paid, the list of Interlocutory Applications(IA), the list of Rejected Cases, the list of Idle/Unprocessed e-Filed cases. So once you e file your case you can keep track of the case digitally using dashboard option without even visiting the court complex.

1.7.New case option:

After you login, you will be welcome d by the dashboard with the filing menu list on the left hand side . In the e filing menu list Click on 'New Case' Option under the dash board which will take you to the form where to file the case .



1.8. Where to file High court /Lower court:

After Choosing the new case option in the dash board page you need to select where you are going to file the case whether in the

☒ HIGH COURT ☐ LOWER COURT

High court or in the Lower court . For filing in the High court choose the radio button for High court and for filing in the lower court choose the radio button of the lower court option . And fill the following details through drop box i.e High court , civil or criminal ,Matter Type, Case Type , and whether it is MACT case or not and whether it is an ordinary or Urgent matter. In case of lower court choose the State, the District, the Court Establishment in addition to the above particulars.

Check all the particulars and if it is correct then click on submit button .If you want to make any corrections then click reset button .

1.9.Filling up of forms:

1.9.1.Colour coding:

The next step is to fill the digital forms generated. Before filling up the forms we need to understand the colour coding used in the forms page which will make our task easier.

- **Blue colour** for the form in use and **Active**
- **Green colour** for the form which is **completed** or **Done** .
- **Orange colour** for the forms which are **optional**;
- **Red colour** for the forms which are **mandatory** to be filled up.

Filing Form

● Active ● Done ○ Optional ● Required

1 Petitioner 2 Respondent 3 Extra Information 4 Extra Party 5 Case Detail 6 Act-Section 7 Subordinate Court
8 Sign Method 9 Upload Document 10 Pay Court Fee 11 Affirmation 12 View

Though there are optional forms and optional fields it is advisable to fill up all the details because only then you can have a complete digital picture of your e filed case. And don't forget that after filling up each and every form click "SAVE" and then "NEXT".



1.9.2. Complainant/Petitioner form:

In the complainant/petitioner form you need to fill up all the details relating to the petitioner. And the fields with red star are mandatory. But it is advisable to completely fill up all the details. For example the mail is given as optional. But only when you fill up email you can get various alerts to your inbox from the eCourts services. Hence fill up all details and click "SAVE" and then "NEXT".

Complainant / Petitioner Information

Organisation: ☐

Complainant / Petitioner*:

Relation of Complainant/Petitioner with relative name*:

Relative Name*:

Date of Birth*:

Age*:

Gender*: ☒ Male ☐ Female ☐ Other

Religion*:

Caste*:

Email:

Mobile*:

Address*:

State*:

District*:

Taluka:

Taluqa:

Ward:

Village:

Pincode:

Police Station Code:

1.9.3.e filing number:

The Saved Form will generate an e Filing Number at the Right Top. It can be noted for your reference.

e-Filing No. EC-KABIFF-00012-2020

1.9.4. Respondent form:

The respondent form is similar to the petitioner form and hence fill up all the details relating to the respondent and click "SAVE" and then "NEXT" ..

After adding all the details you will get the message as respondent added successfully



1.9.5. Extra information Form (optional):

If you wish to fill up any extra information regarding complainant or accused, like the Passport number, Pan card number, Fax number, Phone number Alternate Address it can be filled up under this form. Though this form is optional it is advisable that these all particulars to be filled up as far as possible. After filling up the extra information, click on Save button and; then Click on Next button. But If you do not want to fill the extra

information about the Complainant/Petitioner or Accused/Respondent then directly click on the **Next** button.

1.9.6. Extra Party Details :

The Extra Party information arises in cases where there are more than one parties on the Complainants/Accused side or on the Petitioners/Respondents side or on both sides. Though this Form is also optional, it is highly recommended that it need to be filled up because once this form is submitted it cannot be modified later .

Note: 1. Once you submit this file, can not modify extra party.
2. It is recommended to fill in Extra Party details though not mandatory.

Previous

SAVE

Next

1.9.7 Case Details:

The Case Details Form contain the particulars of Cause of Action Details/ Date/ Dispute Place, the claim amount, Any Important Information/ Subject/ Reason, the Prayer, Relief Particulars.

1.9.7.1. Hide Party:

Hide party is an important option in Case details form. In case of offenses against women and children, POSCO act matrimonial disputes wherever law mandates the protection of the identity of the Victim or petitioner then this option should be enabled so that the privacy of the petitioner will be protected and the mandate of law can be complied with. Hence the identity of the Hide party option enabled person will not be revealed in the digital screens !

1.9.8. Act-Section:

Fill the details of the Act and Section and save the details and then click Next to move to the next form .

1.9.9. Signing Method:

- In the e-signing option, there are three options to sign
- uploaded and later on e signing Using Aadhar
- uploaded using digital signature digital token.
- Uploaded and later on e signing using mobile OTP. You can choose any one option and then proceed further by clicking SAVE and NEXT .

1.9.10. Upload Document:

[illegible]

When you have documents to upload use this option and upload the documents. Choose the document type, document title and attach the document file which should not be more than 50 MB and click upload. The uploaded document will be displayed. If you have wrongly uploaded any document you can use the delete option and delete it. Then, you may upload the correct document. Once all the documents are uploaded, click on **Next** button.

Document Information

Document ID #: Documents Title #:

Title #: to the website.

NOTE: Please upload pdf file only (PDF file name max. length can be 50 characters only. Only digits, characters, spaces, hyphens and underscores are allowed). Max. PDF file is 20MB.

Show 15 entries

#	Document Name	Uploaded Documents	Index	Pages	Remove
1	PETITION	<input type="button" value="BOK/BIFF006122025 PETITION.pdf"/> <input type="button" value="PETITION COPY"/> 760616001122025071406161220250210000470120250706021	1-1	1	<input type="button" value="Delete"/>
2	VAK/LATHANAMA	<input type="button" value="BOK/BIFF006122025 VAK/LATHANAMA.pdf"/> <input type="button" value="VAK/LATHANAMA"/> 760616001122025071406161220250210000470120250706021	1-3	3	<input type="button" value="Delete"/>

Showing 1 to 2 of 2 entries

1.9.11. Pay court fees:

For making payment of court fee you can make online payment or through Challan payment and upload the challan details. After filing up payment details and clicking submit button, then click on **Next** button.

Fee type *:

Fee Amount *:

Payment Mode *:

Bank Name:

Challan/ Cheque/DD/ eChallan No. *:

Date *:

Select Party *:

Upload Receipt *: No file selected.

NOTE : Please upload pdf file only (PDF file name max. length can be 45 characters only. Only alpha, characters, spaces, hyphens and underscores are allowed.) Max. PDF file size 2MB.

1.9.12 Affirmation and Verification of Applicant.

I. Applicant/Complainant/ Litigant Affirmation.

Applicant/Complainant/Litigant Affirmation

[view Applicant/Complainant/Litigant Affirmation](#)

One Time Password (OTP) has been sent to your mobile *****66.

Mobile OTP *:

- Type the Name of the Applicant
- Type the mobile number of the Applicant
- Click on **Send OTP** button. Then, type the OTP received in the mobile number of the applicant and then Click on **Verify OTP** button.

Document eVerified by Mobile OTP ✓

On Date : 02-05-2020 21:29:16 PM

Using Mobile : *****66

By Litigant : RAVINDRA MADHAV

[View eVerification](#)

1.9.13. Advocate Identification and Verification:

- After the e-verification of applicant, then Advocate Identification also to be verified accordingly.
- Type the name of the advocate
- Type the mobile number of the Advocate
- Click on the **Send OTP** button. Then, type the OTP received to your registered mobile number and then Click on **Verify OTP** button.

- After the verification of (i)the applicant and (ii) the Advocate, then Click on the **Next** button.

1.9.14 . View:

After filling up all the details, the filled up form details can be viewed using the 'EXPAND ALL' option or click on + to view the details against each category.

1.10. Final submit:


After checking all the details click the option "FINAL SUBMIT"

Pending Acceptance				
Slrow	ID	Source	Subject	Submitted On
1	EC-KABEET-00010000 ENHANC TEST ENHANC KABEET/ALCA	New Case	KABEET/ALCA KABEET/ALCA	00010000 00:00:00 PM
2	EC-KABEET-00010000 ENHANC TEST ENHANC KABEET/ALCA	New Case	KABEET/ALCA KABEET/ALCA	00010000 00:00:00 PM
3	EC-KABEET-00010000 ENHANC TEST ENHANC KABEET/ALCA	New Case	KABEET/ALCA KABEET/ALCA	00010000 00:00:00 PM

Then Click on the e Filing **Acknowledgment** button

Now, the e filing acknowledgment gets downloaded automatically in PDF form as shown below.



E-Filed			
<div>  <div> <div> E-Filed No Plaintiff Respondent M(u) Attorney E-Filed Admin Payment Details </div> <div> E-Filed No: E-00000000000000000000 Plaintiff: RAVINDRA MADHAV Respondent: RAJESH KUMAR M(u): 0 Attorney: GURU PRASAD (KAR-10000000000000000000) E-Filed Admin: BY ADDL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE BALLARI COMMERCIAL COURT Payment Details: </div> <div> E-Filed Date/Time Matter Nature Currency </div> <div> 00-00-2000-00 00:00:00 Matter Nature Currency </div> </div> </div>			
Generated Date: 00-00-2000			

1.13. Generate Case party details:

Similarly you can generate the case party details by clicking on the case parties option.

The screenshot shows a Firefox download dialog box. The file being downloaded is 'efiling_200607FF000122020.docx' (1.7 KB) from the URL 'https://efiling.accounts.gov.in'. The dialog offers two options: 'Open with' (selected) and 'Save file'. The 'Open with' option is set to 'LibreOffice Writer (default)'. There is also a checkbox for 'Open this automatically for files like this from now on'. The background shows a page with a table of contents for 'e-Filing Guide'.

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR E-FILING TEST,,	
COMEX (COMMERCIAL EXECUTION CASES)	
1	Ravindra Madhava W/o RAMAKRISHNA, Aged about 45 years, Resident of Madhav Transport, Ballari, Bellary, Ballari, Karnataka, India
---Petitioners	
Versus	
1	Rahul Kumar W/o SOMASHEKAR Resident of Amarapura, ballri, Bellary, Ballari, Karnataka, India

1.14. Logout:

Lastly, you can log out from the current session by going to the **Home** in the dashboard and then click on the **log out** icon on the right side top of the screen.



1.15. Conclusion:

Thus you can successfully e file a new case in the online e filing portal which has the added advantage of keeping track of the status of the case digitally through Dashboard options. So keep e filing new cases through e filing portal and join the new band of 'Digital Era Advocate'.

-----Start e filing new cases in www.efiling.ecourts.gov.in -----.

www.efiling.ecourts.gov.in

e-Filing



Welcome,
VENKATESH
THUGAURI

Fast Login
IP Address

- Home
- New Case
- Documents
- Deficit Court Fee
- Interim Application
- Reports
- Contacts
- News & Events

My e-Filing Status

29 Draft	17 Pending Scrutiny
3 Defective	0 Not Accepted
0 Defective	0 Defective

My e-Filed Cases

0 e-Filed Cases	0 e-Filed Documents
0 Rejected Cases	0 e-Filed Documents
0 Deficit Court Fee	0 IA

**ONLINE EFILING PORTAL
FOR HIGHCOURTS &
DISTRICT COURTS IN INDIA**

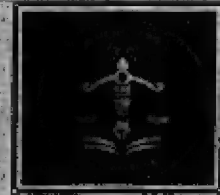


eCommittee
Supreme Court of India



eCommittee
Supreme Court of India

Register for efilng for High courts/District courts in India And Become a Digital Era- Advocate



Are you an advocate practicing in High court / District court of India ?

Do you want to file your case in the comfort of your office !

Do you want to file your case without visiting court complex !

Then choose *efiling* -the digital online filing process.

10 step Registration procedure for Advocate
at efilng portal www.efiling.ecourts.gov.in

Visit efilng portal www.efiling.ecourts.gov.in and become a registered user by following the 10 steps hereunder

GETTING STARTED

Before starting registration keep the following details ready

- (i) Details of your mobile number, email ID registered with court database
- (ii) Details of your bar enrolment number
- (iii) Digital Photo in Jpeg/Jpg format of size of size between 5KB and 5 MB
- (iv) Identity proof (Any one Pan card /aadhar card/ Voter card/ Driving license/ Bar Registration certificate formate of size between 5KB and 5 MB
- (v) Smartphone/laptop with internet connection

As it is a time bound registration you need to complete within 18 minutes

Dont start registration without having all the above details ready !

Lets start Registration

STEP 1: Visit www.efiling.ecourts.gov.in



STEP-2 Select your < state >

- (i) by clicking on the drop list (or)
 (ii) by clicking the state directly from the India map

**STEP 3: Click "Register" in the login page**

STEP 4: Select the radio button "Advocate"
 in the registration form

STEP 5: Fill up the following details

- Mobile Number*
- Email ID*
- (* The mobile number and the email ID that is registered with the court where the advocate practices must be furnished . If mobile number and email id are not registered with court database then registration will not be completed and in that case contact concerned court for registering the same.)
- Bar Registration Number of the Advocate.
- Choose User ID (your preferable choice)
- Choose where you are Enrolled
- High Court/ court establishment
- Choose the Highcourt
- Enter the captcha
- Click "GET OTP"

Step 6: Check your registered mobile number and the registered email ID for OTP. You should receive 2 separate OTP in your mobile number and the email ID. In some cases you may receive one OTP in your mobile number alone, in that case enter the OTP received in your mobile number and proceed further.

STEP 7: Two OTP verification: If you have received Two OTPs: Enter the OTP received in your mobile number and the OTP received in your email id in the respective entry bar and click verify OTP.

(OR)

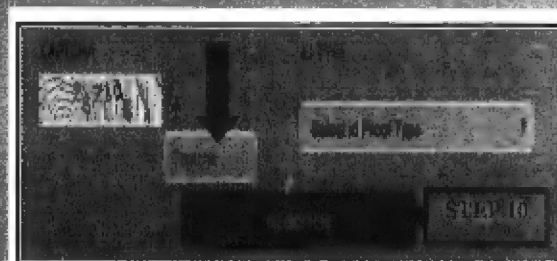
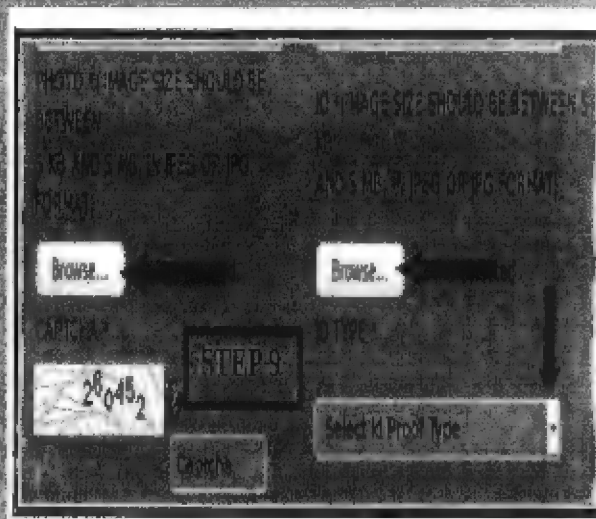
Step 7: One OTP verification: In some cases if you have received one OTP in your mobile number alone, then enter that OTP in the mobile OTP entry bar and click verify OTP.

STEP 8: Fill other Details

- Password
- (Password must contain minimum 8 digit and must include 1 uppercase character, 1 lowercase character, 1 number, 1 special character)
- Confirm password
- First name
- Last name
- Other contact number
- Gender
- Date of Birth (DD/MM/YYYY)
- Address line 1
- Address line 2
- City
- State
- Pincode

Step 9 Upload your Photo and ID

- Upload your Photo (in .jpeg/.jpg format of size less between 5 KB and 5 MB) using 'Choose file' option.
- Upload Identity proof in image size less than 5 KB and 5 MB using the 'Choose file' option.
- Suppose you don't have digital photograph just take a photo from your smart phone and upload.
- Similarly, if you don't have digital copy of your ID cards then you can take a photo or scan the ID cards using any scan application and upload. Before uploading ensure that your photo and the ID card are in the format .jpeg or .jpg and in size between 5 KB and 5 MB.
- Then you have to choose the type of ID card uploaded i.e. Pan card/ aadhar card/ voter Card/Driving license/Bar registration certificate from the drop down box.



STEP 10: Finally enters the captcha code given in box and click the "Register" button to complete the Registration process.

You will finally get the message

"Registered successfully"

Registered successfully

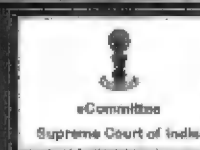
You have successfully become a registered Advocate of e-filing .

Welcome to the digital world of e-filing of High courts /District courts of India .

Start e-filing your cases from the comfort of your office



**Organized by
eCommittee, Supreme Court of India**



APPENDIX-III

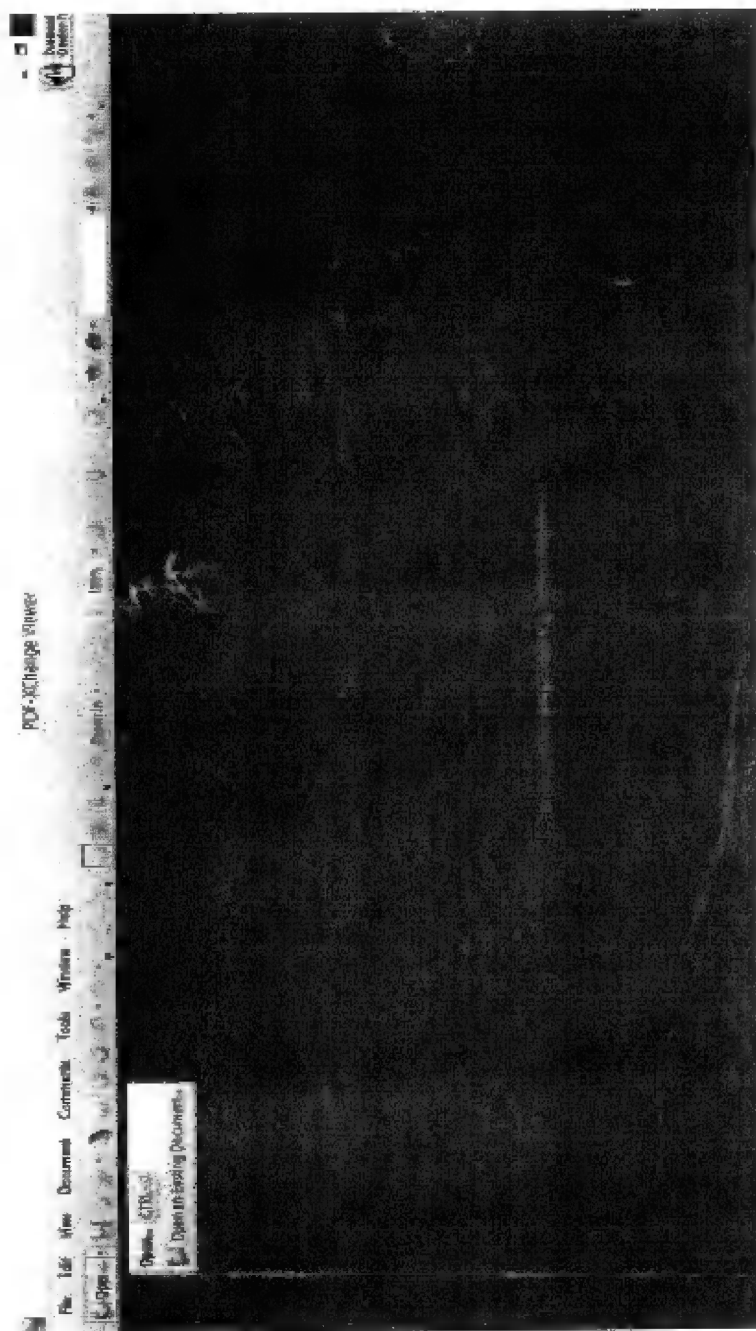
**Procedure for
converting a document
into an OCR searchable
PDF.**

There are many free & trial version software available online that can be downloaded from internet for creating OCR in PDF files. These includes PDF -XChange viewer, Acrobat Adobe, Abbyy FineReader etc.

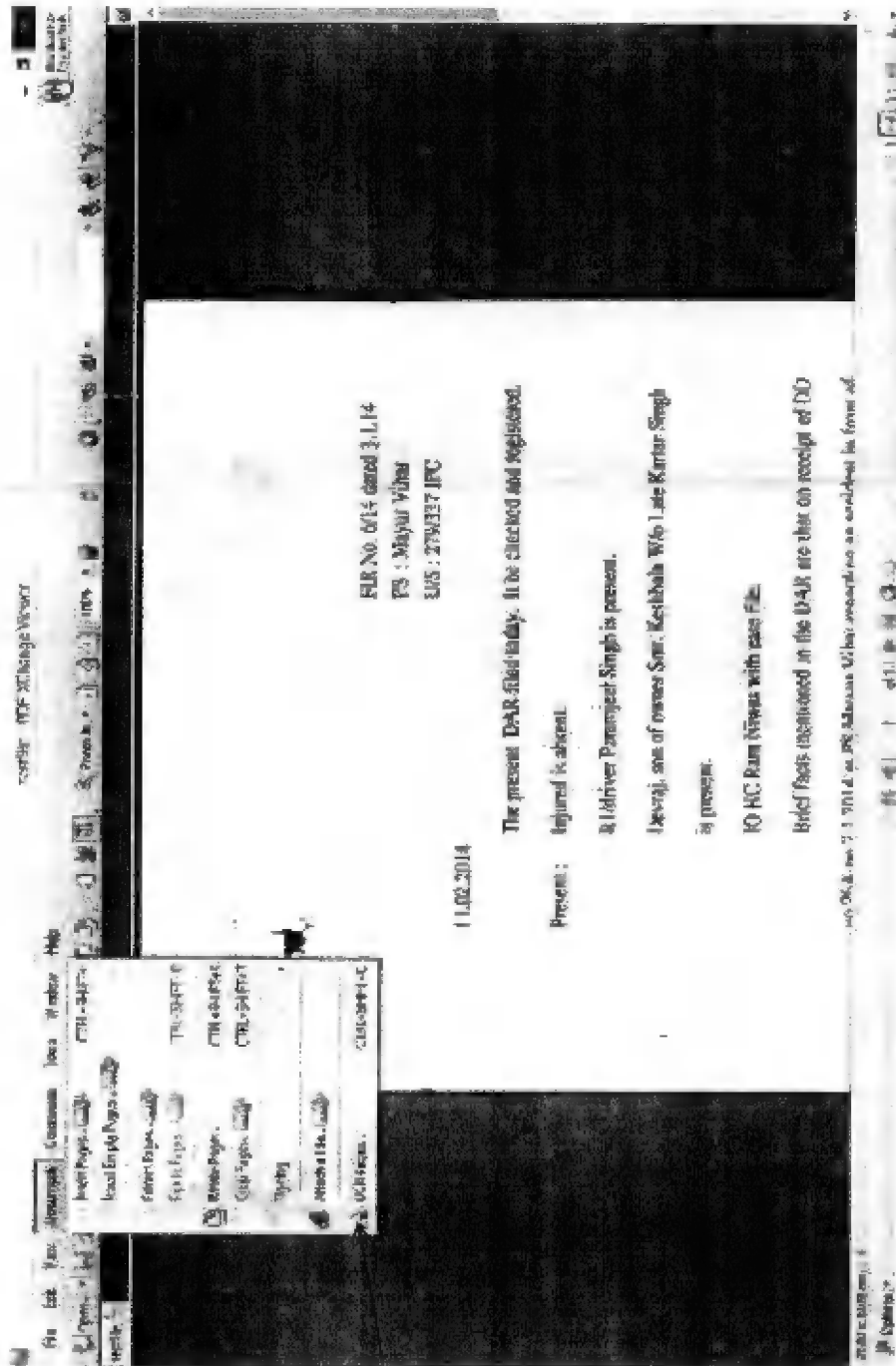
Open the PDF file containing a scanned image you wish to Convert in OCR Format

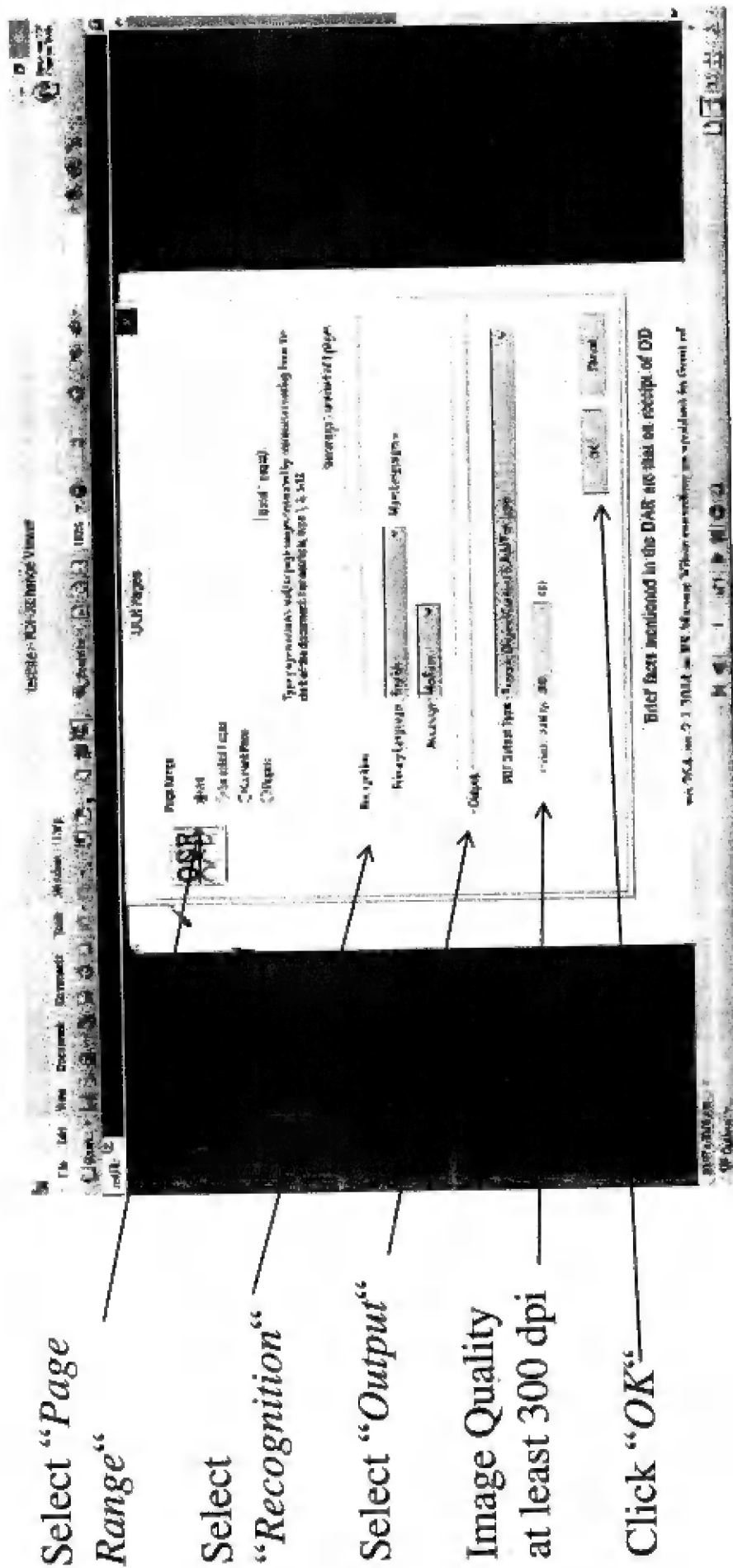
Using PDF- XChange Viewer – free

From the main menu, select
“Open” →
“Open an Existing Document” →
 Open any PDF Document.

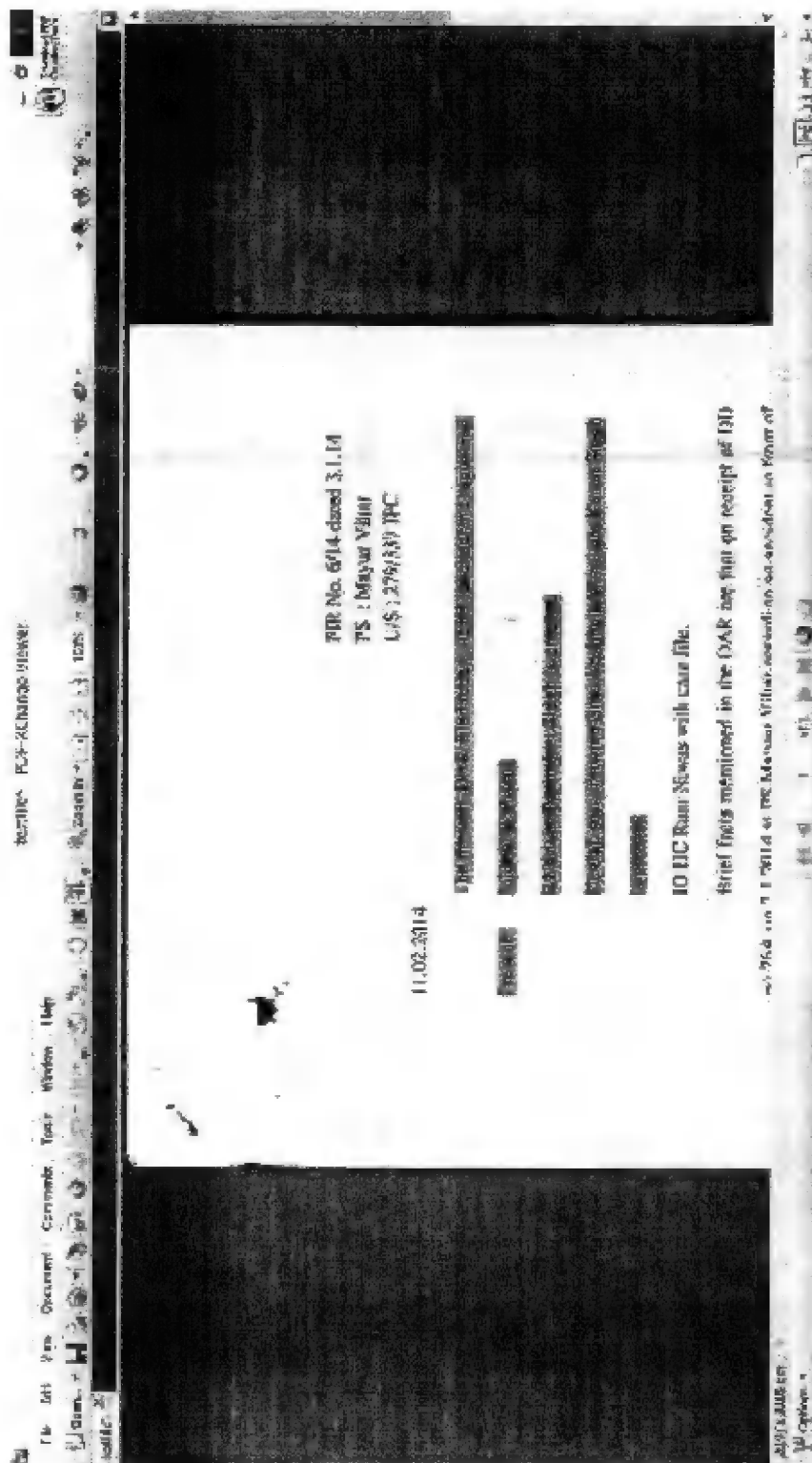


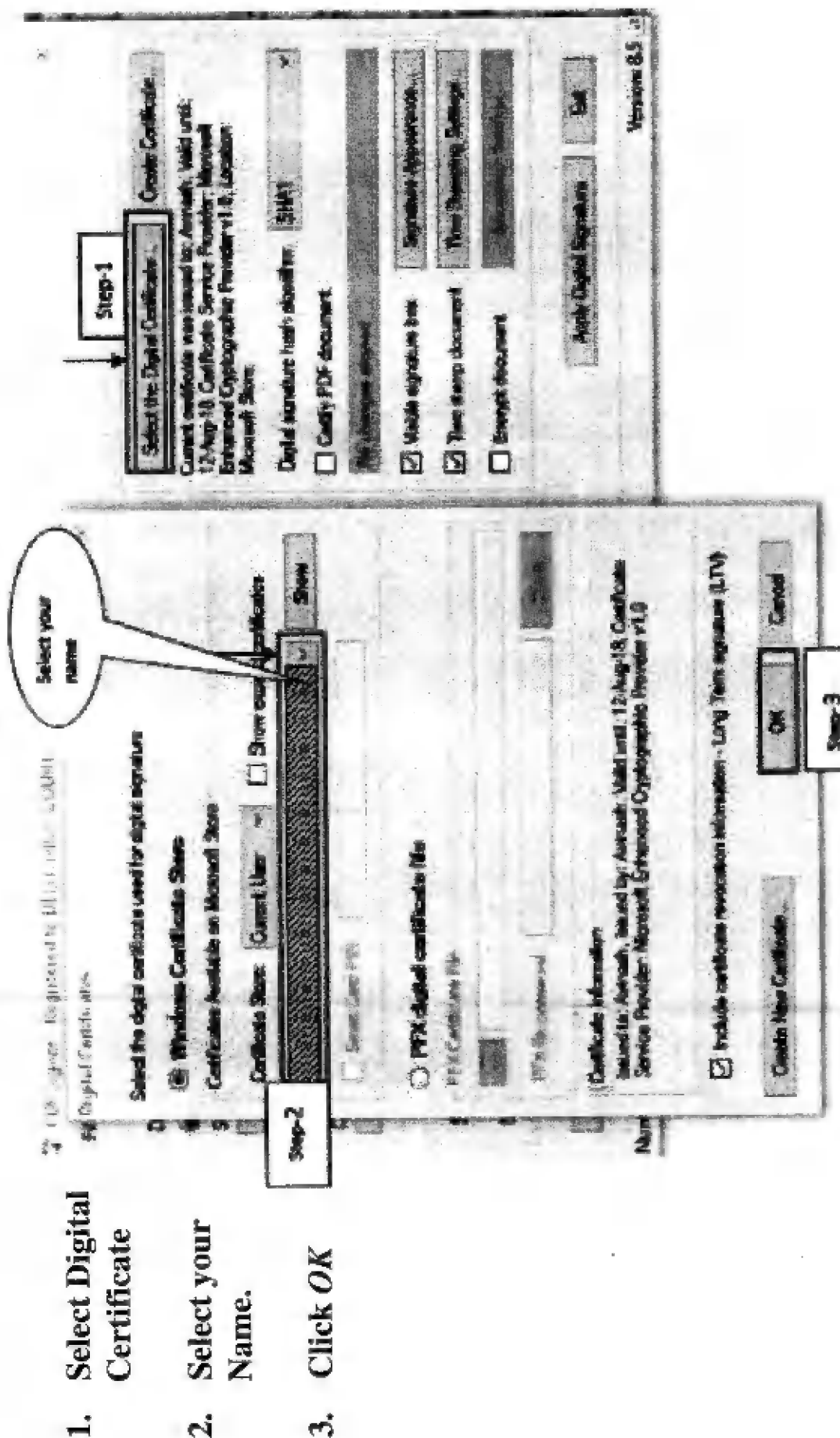
From the main
menu, select
"Document" →
"OCR Pages".





Document in OCR Format

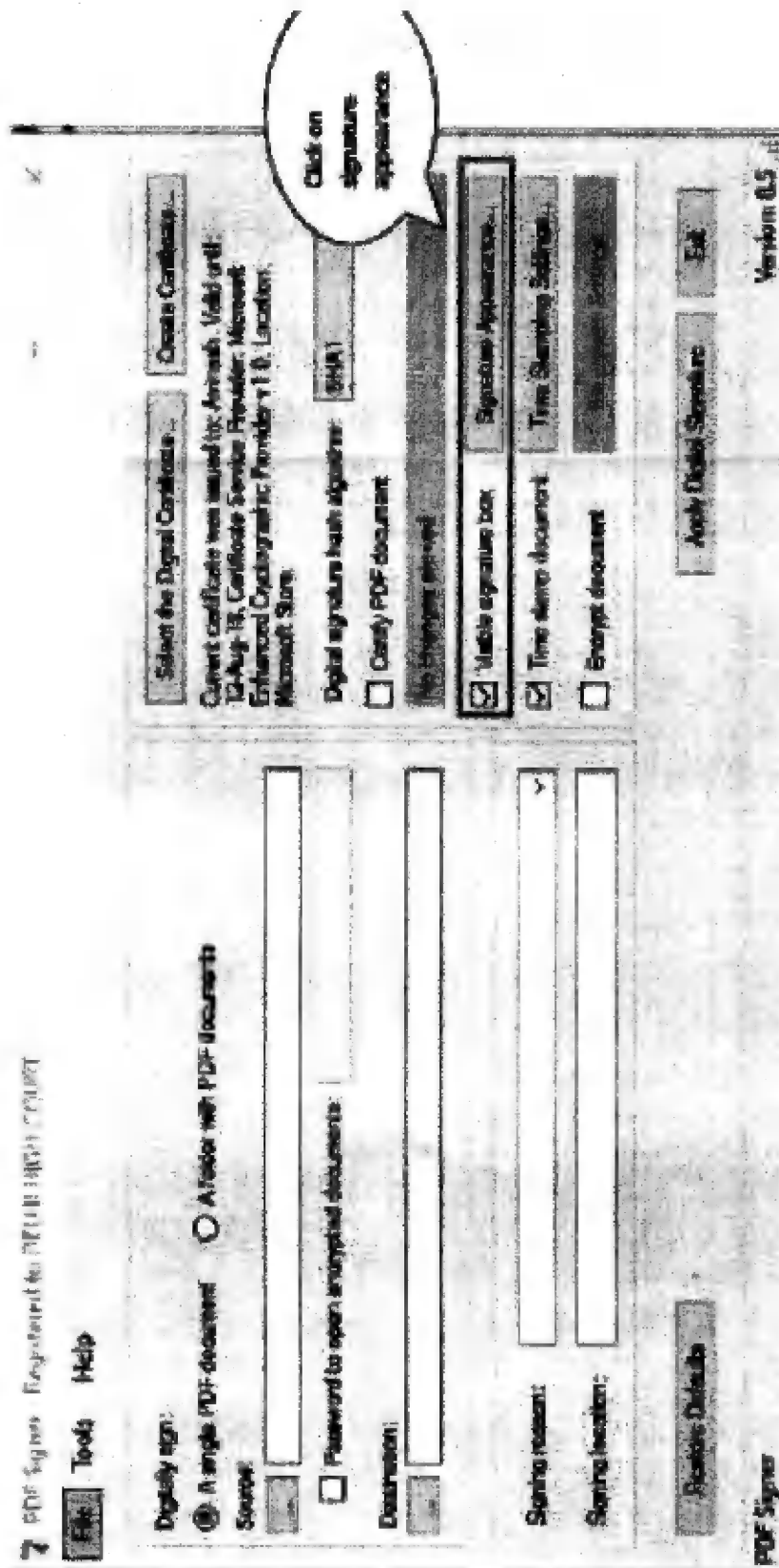




1. Select Digital Certificate

2. Select your Name.

3. Click OK



Configure Signature Appearance

Signature Page: All Pages

Position: Bottom Left

☐ Large signature box

☒ Custom position

X-axis: 30 Width: 16

Y-axis: 30 Height: 50

☐ Place an image on the signature box

Font:

☒ Include Adobe signature status images (e.g. question mark, green tick)

☐ Font size: 10

☐ Right to Left text

Standard font: Times-Roman

☐ Use a custom font

Configure Signature Box:

☒ Name from digital certificate

☐ Entire certificate subject

☐ Reason

☒ Signing Date

☒ Labels

☒ Date format: DD/MM/YYYY HH:MM:SS

☐ Location

Labels:

☒ Signed By:

☐ Location:

☐ Reason:

☐ Signing Date:

Image and text:

☒ Image and text

☐ Image as background

☐ Image with no text

Restore Defaults

OK **Cancel**

Digitally signed by:

File Tools Help

Digitally sign:

☐ A single PDF document ☒ A folder with PDF documents

Source:

☐ Password to open encrypted documents:

Destination:

Signing reason:

Signing location:

Number of PDF documents: 2

Current certificate was issued to: Javed Akhtar, Valid Until: 29-Dec-19, Certificate Service Provider: Microsoft Enhanced RSA and AES Cryptographic Provider, Location: Microsoft Store.

Digital signature hash algorithm:

☐ Certify PDF document

☒ Visible signature box

☒ Time stamp document

☐ Encrypt document

Version: 8.5

1. Go to
Destination
Folder &
check
Digitally
signed PDF
File

2. PDF File After
Digital
Signature

3. Digital
Signature



APPENDIX - V

There are many free software program available online that can be downloaded from internet for creating bookmarks in PDF files. These includes Foxit Reader, Abbyy FineReader, Adobe Acrobat etc.

Foxit Reader(Using for Bookmark)

Download the software from website

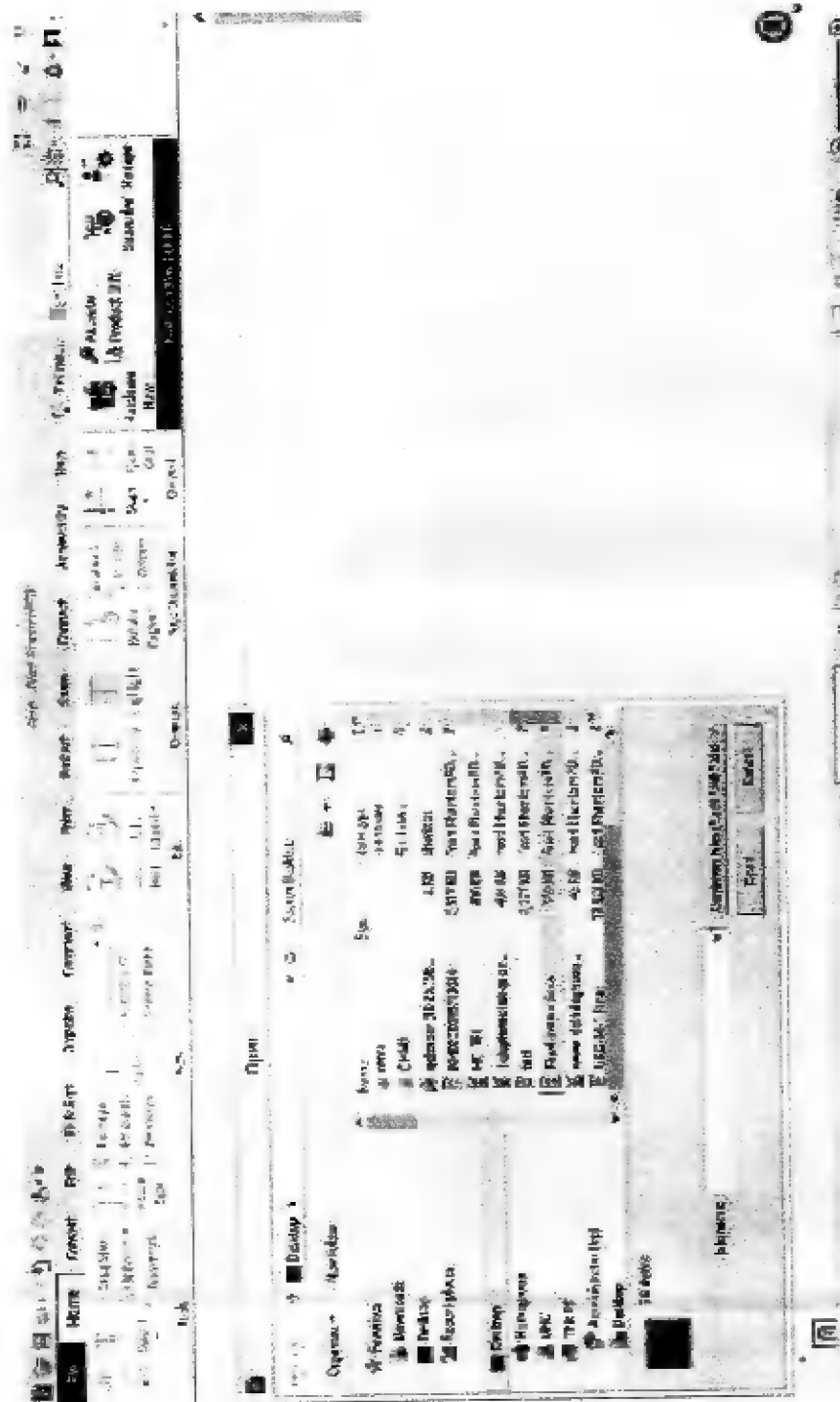
<https://www.foxitsoftware.com/pdf-reader>. The software program may be downloaded by clicking on Free Foxit Reader Download link available on website.



Open the PDF file to Bookmark

Using Foxit Reader – free trial

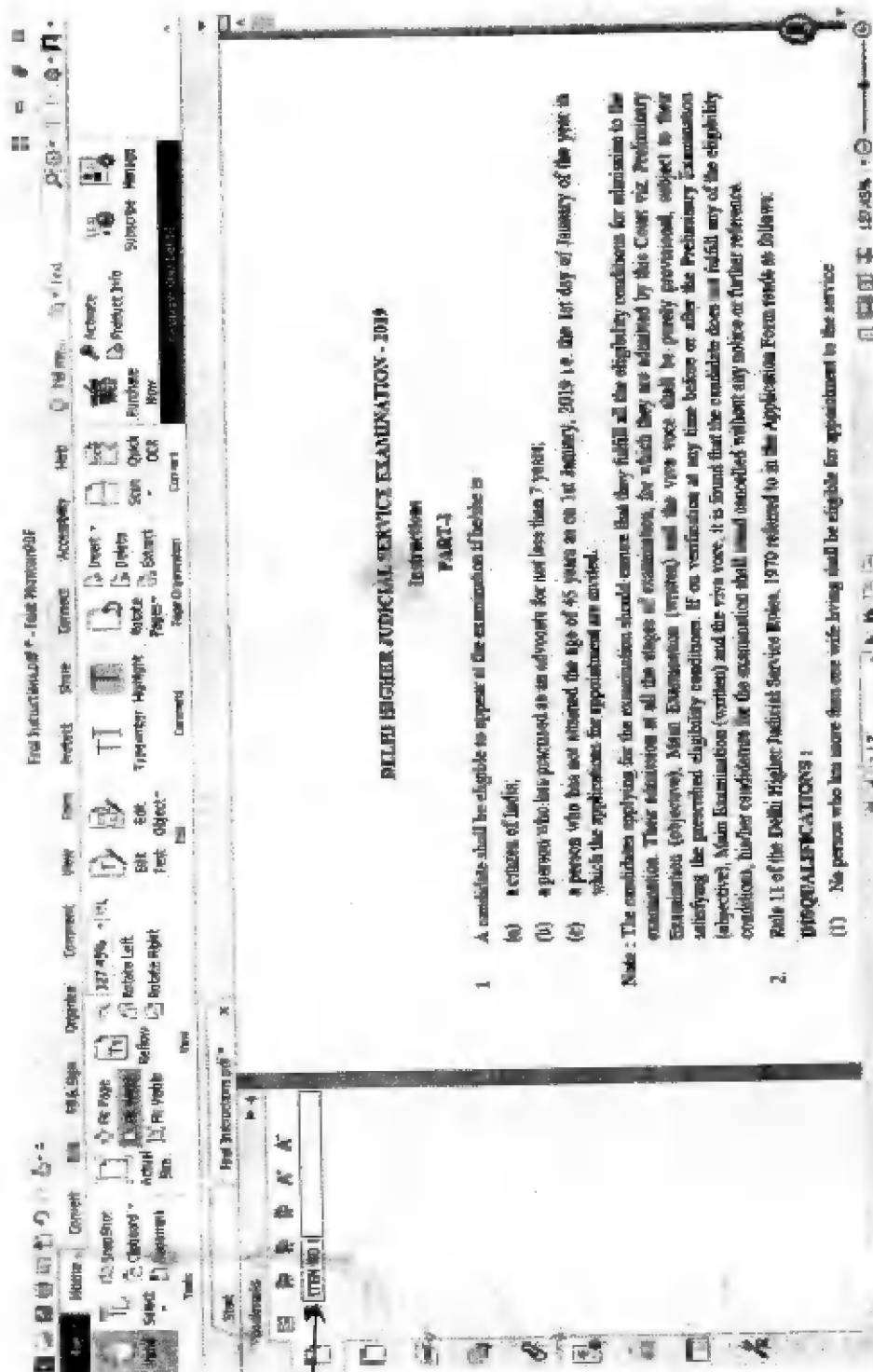
Select & open
the PDF
document to
make
bookmark



Using Foxit Reader – free trial

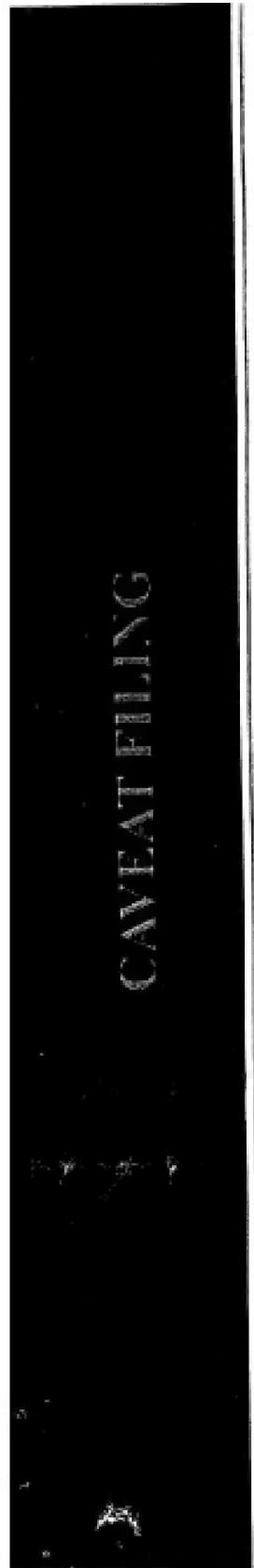
1. Type the name of your Bookmark

2. By default, the newly created bookmark will point to the start of the current page.



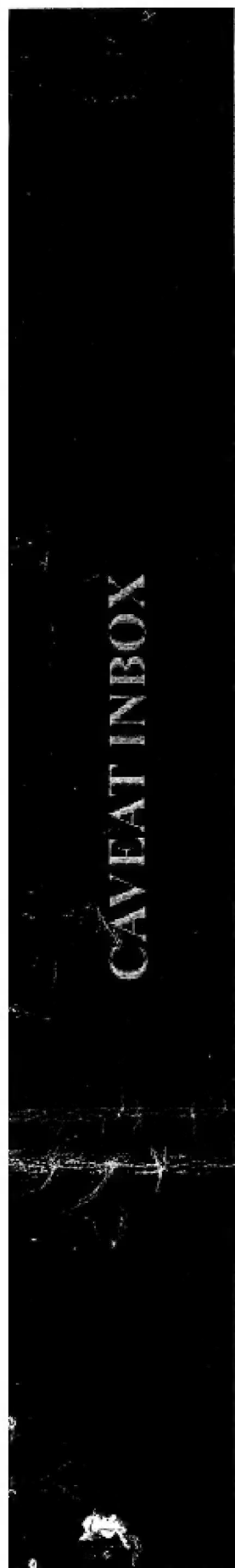
APPENDIX-VI

Procedure for filing Caveat



In this you can do Document filing in the already filed matter.

- 1) There is a submenu Caveat available in e-Filing menu.
- 2) Select Case Type
- 3) Enter Caveator's & Non-Caveator's Details
- 4) Enter Impugned Order details
- 5) Add e-court fee
- 6) Select document to be upload
- 7) Click on Save button to submit the Filing.



INBOX: Now you can track the status of Caveat through your inbox.

1.) Click on the Caveat
Inbox sub menu under
Inbox menu

2.) under Caveat Inbox
there are two tabs viz

SCRUTINY--- Lists the
cases which are in scrutiny
stage

DEFECTIVE--- Lists the
cases which are in
defective stage

HIGH COURT OF DELHI e-Filing Management System

Search By: ALL

SCRUTINY (2)

DEFECTIVE (1)

SlNo	Diary No.	Case Type	Case No.	Caveator Vs Respondent	Memo of Party	Date of Filing	Status
1	435022/2020	CS(COMM)	/0	CAVEATOR VS NON CAVEATOR	Memo of Party	09-05-2020	SCRUTINY
2	435002/2020	CS(COMM)	/0	RESPONDENT 1 Vs TEST 1	Memo of Party	09-05-2020	SCRUTINY

PROFILE

e-Filing

Inbox

6. Caveat Case Inbox

7. Application Inbox

8. Document Inbox

10. Previously Filed Cases

11. Draft Inbox

CHANGE PASSWORD

LOGOUT